

प्रेषक,

डी०एस० गर्बाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 18 जनवरी, 2013

विषय:-जनपद गढ़वाल के सुमाडी में एन०आई०टी० की स्थापना हेतु 102.841 है० भूमि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं०-118/8 ए०एल०सी०(2011-12) दिनांक-05.10.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद गढ़वाल के सुमाडी में नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एन०आई०टी०) की स्थापना हेतु आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित ग्राम (सुमाडी, स्यारमल्ला, बगवान चडिगांव, नयालगढ़, सुपाणा लगाखालू व नकोट, लगाखालू) के खसरा संख्याओं में अंकित कुल 102.841 है० राजस्व भूमि, वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15.2.2002 में निहित प्राविधानों एवं प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

14

- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- 8- उक्त भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-132 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में दिये गये निर्णय का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० गब्याल)
सचिव।

पृ०प०संख्या-35 /समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- उप निदेशक, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, श्रीनगर, गढ़वाल।
- 5- निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय देहरादून।
- 6- प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय देहरादून।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(संतोष बडोनी)
अनुसंधान।